

हट्टी समुदाय

हाल ही में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के सरिमौर ज़िले के तान-गरी क़्षेत्र के हट्टी समुदाय को आदवासी का दर्जा देने पर वचिार कर रही है ।

हट्टी समुदाय:

- हट्टी एक घनषिठ समुदाय है, जसिे कसूबों में 'हाट' नामक छोटे बाज़ारों में घरेलू सबज़यिीं, फसल, मांस और ऊन आदबिेचने की परंपरा से यह नाम मलिा है ।
- हट्टी समुदाय में पुरुष आमतौर पर समारोहों के दौरान एक वशिषिठ सफेद टोपी पहनते हैं ।
- यह समुदाय सरिमौर से गरिि और टोंस नामक दो नदयिीं द्वारा वभिाजति हो जाता है ।
 - टोंस इसे उत्तराखंड के जौनसार बावर क़्षेत्र से वभिाजति करती है
 - वर्ष 1815 में जौनसार बावर क़्षेत्र के अलग होने तक उत्तराखंड के ट्रांस-गरी क़्षेत्र और जौनसार बावर में रहने वाले हट्टी कभी सरिमौर की शाही रयिासत का हसििसा थे ।
- ट्रांस-गरी और जौनसार बावर में समान परंपराएँ हैं तथा अंतरजातीय-वविाह आम बात है ।
- हट्टी समुदायों के बीच एक कठोर जाति वयवस्था है- **भट और खश उच्च जातयिीं हैं, जबकि बधोई उनसे नीची जाति है । अंतरजातीय वविाह अब परंपरागत रूप से सख्त नहीं रहे हैं ।**
 - हट्टी समुदाय '**खुंबली**' नामक एक पारंपरिक परषिद द्वारा शासति है, जो **हरयिाणा के खाप पंचायत** की तरह सामुदायिक मामलों को देखती है ।
 - **पंचायती राज वयवस्था** की स्थापना के बावजूद खुंबली की शक्ति को कोई चुनौती नहीं मलिी है
- **सरिमौर और शमिला** क़्षेत्रों की लगभग नौ वधिानसभा सीटों पर उनकी अचछी उपस्थति है ।
 - भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की कुल आदवासी आबादी 3,92,126 है, जो राज्य की कुल आबादी का 5.7% है ।

उनकी मांगें:

- **जनजातीय दर्जा:**
 - वे वर्ष 1967 से **अनुसूचति जनजातिका दर्जा** देने की मांग कर रहे हैं, जब उत्तराखंड के जौनसार बावर में रहने वाले लोगों को आदवासी का दर्जा दयिा गया था, जसिकी सीमा सरिमौर ज़िले से लगती है ।
- **चुनौतयिीं:**
 - **स्थलाकृतिक नुकसान** के कारण हिमाचल प्रदेश के कामरौ, संगरा और शलियिाई क़्षेत्रों में रहने वाले हट्टी शक्ति तथा रोज़गार दोनों में पछिड गए हैं ।

भारत में अनुसूचति जनजातयिीं की स्थति:

- **परचिय:**
 - 1931 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचति जनजातयिीं को "बहषिकृत" और "आंशकि रूप से बहषिकृत" क़्षेत्रों में रहने वाली "पछिडी जनजातयिीं" कहा जाता है । **वर्ष 1935 के भारत सरकार अधनियिम ने पहली बार प्रांतीय वधिानसभाओं में "पछिडी जनजातयिीं" के प्रतनिधियिीं को बुलाया ।**
 - संवधिान अनुसूचति जनजातयिीं की मान्यता के मानदंडों को परभिाषति नहीं करता है, इसलयिे वर्ष 1931 की जनगणना में नहिति परभिाषा का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में कयिा गया था ।
 - हालाँकि संवधिान का अनुच्छेद 366 (25) केवल अनुसूचति जनजातयिीं को परभिाषति करने के लयिे प्रक्रयिा प्रदान करता है: "अनुसूचति जनजातयिीं का अर्थ ऐसी जनजातयिीं या जनजातीय समुदायों या जनजातयिीं या जनजातीय समुदायों के कुछ हसििसों या समूहों से है जनिहें संवधिान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचति जनजातयिीं माना जाता है ।
 - **342(1): राष्ट्रपति कसिी भी राज्य या केंद्रशासति प्रदेश के संबंध में**, जबकि राज्य के संदर्भ में राज्यपाल के परामर्श के बाद सार्वजनिक अधसिुचना द्वारा उस राज्य या संघ राज्य क़्षेत्र के संबंध में जनजातयिीं या जनजातीय समुदायों के हसििसे या जनजातयिीं या जनजातीय समुदायों के भीतर के समूहों को अनुसूचति जनजातयिीं के रूप में नरिदषिठ कर सकता है ।
 - **705 से अधिक जनजातयिीं** हैं जनिहें अधसिुचति कयिा गया है । **सबसे अधिक संख्या में आदवासी समुदाय ओडशिा** में पाए जाते हैं ।

- संवधान की पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिये प्रावधान करती है।
- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
- कानूनी प्रावधान:
 - असपुशयता के खिलाफ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
 - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
 - पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक वसति) अधिनियम, 1996
 - अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
- संबंधित पहल:
 - भारतीय जनजातीय सहकारी वणिणन विकास परसिंघ (TRIFED)
 - जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन
 - विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह
 - प्रधानमंत्री वन धन योजना
- संबंधित समितियाँ:
 - शाशा समिति (2013)
 - भूरिया आयोग (2002-2004)
 - लोकुर समिति (1965)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न स्टैंडअप इंडिया योजना के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
2. यह सडिबी के माध्यम से पुनर्वतित प्रदान करता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

- इस योजना को अप्रैल 2016 में आर्थिक सशक्तिकरण और रोज़गार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए मीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये लॉन्च किया गया था। अतः कथन 1 सही है।
- महिलाओं तथा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ताकतव्यापार, वनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने को तैयार एवं प्रशिक्षण दोनों प्रकार के उधार लेने वालों की मदद की जा सके।
- प्रमुख विशेषताएँ:
 - नई (ग्रीनफील्ड) परियोजना की स्थापना के लिये 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण प्रदान करना।
 - कार्यशील पूंजी के आहरण के लिये डेबिट कार्ड (रुपे)।
 - उधारकर्ता का साख पृष्ठभूमि तैयार करना।
 - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशिके साथ पुनर्वतित वणिजन। अतः कथन 2 सही है।
 - नेशनल क्रेडिट गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) के माध्यम से क्रेडिट गारंटी के लिये 5,000 करोड़ रुपए के कोष का निर्माण।
 - पूर्व-ऋण प्रशिक्षण आवश्यकताओं, ऋण की सुवधि, मध्यस्थ, मार्केटिंग आदि के लिये व्यापक समर्थन के साथ उधारकर्ताओं हेतु समर्थन जुटाना।
 - ऑनलाइन पंजीकरण और सहायता सेवाओं के लिये वेब पोर्टल। अतः विकल्प (C) सही उत्तर है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

